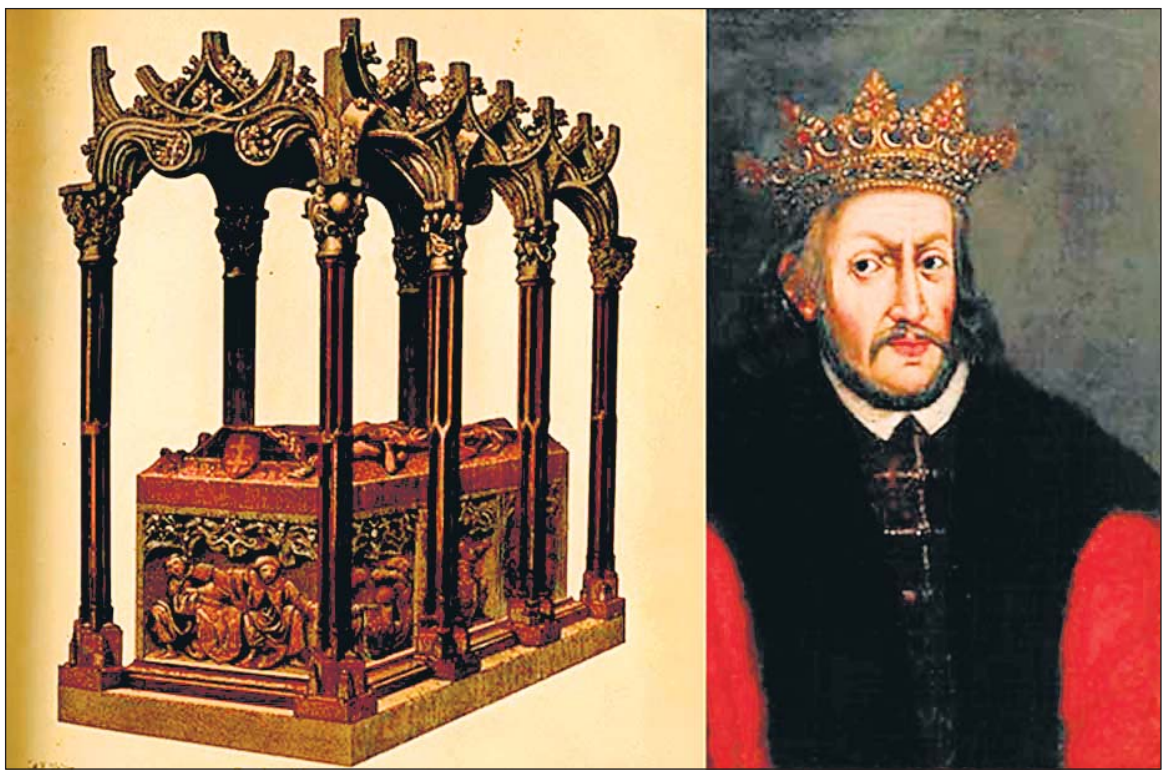

कहानी किंग कैसीमीर के अभिशाप की है। कैसीमीर चतुर्थ, एण्ड्रू यैग्यलोनियन पोलैंड के सबसे सफल शासकों में से एक था उसने 13 साल चले युद्ध में कैथलिक धार्मिक व्यवस्था, टूटॉनिक के योद्धाओं को हराया था और पैलैण्ड के सबसे महत्वपूर्ण शहर, बाल्टिक सी के तट पर स्थित पॉमरेनिया को वापस ले लिया था। वर्ष 1492 में कैसीमीर की मृत्यु के बाद उसे वावेल कथीड्रल के होलीक्रॉस चैपल में दफनाया गया। सन् 1565 में उसकी पत्नी एलिज़ाबैथ को भी यहीं दफनाया गया। यह मकबरा गॉथिक आर्ट के बेहतरीन नमूनों में से एक है। पत्थर का ताबूत लाल मार्बल से बना है। इसके ऊपर लाइमस्टोन की कलात्मक मेहराबदार छतरी है, जिसे सहारा देने के लिए मार्बल के स्तंभ हैं। मकबरे के ऊपर कैसीमीर की लेटी हुई आदमकद मूर्ती है। वर्ष 1975 में कैसीमीर व उसकी पत्नी एलिज़ाबैथ की कब्र खोली गई। बारह वैज्ञानिकों की एक टीम कब्रों के अंदर गई। कब्रों के अंदर जाने का लक्ष्य था, उन्हें संरक्षित करना। वैज्ञानिकों को कब्र में लकड़ी के सड़े ताबूत तथा कैसीमीर व एलिज़ाबैथ के शव मिले। मकबरे की मरम्मत के बाद 18 सितम्बर 1973 को कैसीमीर व उसकी पत्नी के शव एक समारोह में पुनः कब्र में रख दिए गए। लेकिन इसके बाद शुरु हुआ एक अजीब सिलसिला। कब्र में घुसने वाले वैज्ञानिक एक के बाद एक रहस्यमय बीमारी से मरने लगे। सबसे पहला शिकार बना वावेल का एक आर्किटैक्ट, जिसे 1974 में लकवा मार गया और फिर वह मर गया। दस महीनों के अंदर सभी 12 विशेषज्ञ और वहां काम करने वाले 15 मजदूर भी मर गए। इस घटना की तुलना तूतनखामन के श्राप से की जाने लगी। उसकी कब्र में प्रवेश करने वाले कई लोग भी कुछ वर्षों के अंतर में मर गए थे। वैज्ञानिकों का मत था कि, ये सभी मौतें "एस्पर्जिलस फ्लैवस" नाम की एक फंगस की वजह से हुई हैं, जिनसे कई खतरनाक रसायन निकालते हैं। शवों या सड़ रही चीजों पर मिलने वाली यह फंगस मिस्र की कई अन्य प्राचीन ममीज़ पर भी मिली है। मिस्र के चिकित्सक डॉ. एज़ेद्दीन ताहा ने कहा कि, मरने वाले अधिकांश वर्कर्स में फंगस संक्रमण मिला। तथापि, कई शोधकर्ता फंगस के कारण मृत्यु होने को विवादास्पद मानते हैं क्योंकि, उन मरीजों का ना तो पर्याप्त रिकॉर्ड है और ना ही उनका शव परीक्षण हुआ था।

अपने मंत्रियों के विरोध के कारण मु.मंत्री गहलोत को पीछे हटना पड़ा

और अंततः ए.सी.बी. के डी.जी. ने विवादित आदेश वापस लिया

- **उक्त आदेश में भ्रष्टाचार के आरोपियों की पहचान गुप्त रखने का निर्देश था और मुख्यमंत्री गहलोत ने भी इस आदेश का समर्थन किया था।**
- **पर विपक्ष के नेता ही नहीं, बल्कि सरकार के मंत्री भी खुलकर इस आदेश के विरोध में आ गए।**

जयपुर, 6 जनवरी (का.प्र.)। भ्रष्टाचारियों का चेहरा और नाम छिपाने वाले एंटी करप्शन ब्यूरो (ए.सी.बी.) के ऑर्डर को भारी विरोध के कारण दो दिन में ही वापस लेना पड़ा है। इस आदेश के बाद मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच के मतभेद उभरकर सामने आ गए थे। पूर्व मंत्री तथा विधायक भरत सिंह ने तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कार्यवाहक डी.जी. हेमंत प्रियदर्शी को ए.सी.बी. से हटाने की मांग भी कर डाली थी।

इस आदेश का बचाव करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था, कई मामले ऐसे होते हैं, जिसमें अफसर को झूठा फंसाया जाता है, उसे बदनामी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि, जब तक यह साबित न हो जाए कि उसने भ्रष्टाचार किया है, उसकी पहचान गुप्त रखी जाए। यह सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों का फैसला है। जबकि मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास, भंवर सिंह भाटी सहित कई कांग्रेस नेताओं ने ही इस आदेश का विरोध किया था। भाजपा ने भी स्पष्ट रूप से चेतावनी दे दी थी कि, यह आदेश वापस नहीं हुआ तो सदन में विरोध किया जाएगा और कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी।

सरकार के अंदर लगातार बढ़ते विरोधाभास के बीच शुक्रवार शाम को ए.सी.बी. के डी.जी. हेमंत प्रियदर्शी ने नया आदेश जारी करते हुए पुराना आदेश वापस ले लिया है। ज्ञातव्य है कि, हेमंत प्रियदर्शी ने 2 दिन पहले ट्रैप किए गए कथित भ्रष्ट अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम-फोटो जारी नहीं करने के ऑर्डर जारी किए थे।

ए.सी.बी. डी.जी. ने शुक्रवार शाम को इस आदेश को वापस ले लिया, लेकिन इसके दो दिन पहले उन्होंने जो आदेश जारी किया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर नाम और फोटो सार्वजनिक नहीं करने की बात कही गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचारियों का नाम छिपाने का कभी कोई आदेश जारी किया ही नहीं था।

ए.सी.बी. के डी.जी. हेमंत प्रियदर्शी ने जिस आदेश का हवाला दिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि घूसखोर की पहचान छिपानी चाहिए।

ए.सी.बी. के आदेश के खिलाफ खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा था, मेरा यह मानना है कि एंटी करप्शन ब्यूरो का चार्ज लेते ही जो ऑर्डर निकाला, वह ऑर्डर रिजैक्ट होने वाला ही है। मैं उस ऑर्डर से सहमत नहीं हूँ। कोई भी कांग्रेस का विधायक, मंत्री इस तरह की कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगा। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या इस तरीके के डी.जी. के ऑर्डर को मान सकते हैं? खाचरियावास ने कहा था, सरकार इस तरह के ऑर्डर के साथ नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, जिससे हमारे पूरे किए हुए काम पर पानी फिर जाए, हमने कांग्रेस सरकार की नीयत आपको बता दी।

विवादित आदेश में साफ किया गया था कि जब तक आरोपी पर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसकी फोटो और नाम मीडिया में या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। साथ ही, जिस भी आरोपी को पकड़ा जाएगा, उसकी सुरक्षा और मानवाधिकार की जिम्मेदारी ट्रैप करने वाले अधिकारी की रहेगी।

भारत जोड़ो यात्रा को वैस्टर्न.....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नरेन्द्र शर्मा, नरेश शर्मा, अंबरीश भगोत्रा, सुभाष भगत, संतोष मन्हास, बद्रीनाथ शर्मा, वरुण भगोत्रा, अनुराधा शर्मा, विजय तरग्रोत्रा तथा चन्द्रप्रभा शर्मा (डी.ए.पी. की पूर्व महिला नेता)।

रमेश ने कहा कि दो और नेता भी पार्टी में फिर से शामिल होंगे। उन्होंने कहा, "यह पहली खेप है। .....और लोग जल्दी ही (पार्टी में) शामिल होंगे।"

वेणुगोपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के समान विचार वाले सभी "राजनैतिक दलों" के लोग यात्रा, जो कि "देश का एक बड़ा आंदोलन बन चुकी है", में शामिल हो रहे हैं।

ताराचन्द ने कहा कि कांग्रेस छोड़ना उनके राजनैतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने कहा कि वह जल्दबाजी में उठाया गया एक गलत कदम था। उन्होंने कहा, "मित्रता और भावुकता मुझे बहा ले गई थीं।"

जहाँ तक पीरज़ादा का प्रश्न है, कांग्रेस को छोड़ देने के लिये उन्होंने जम्मू-कश्मीर की जनता एवं कांग्रेस से माफी माँगी।

ताराचन्द ने कहा, "हमने अपना पूरा जीवन कांग्रेस में गुजारा था। लेकिन इसी बीच, एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई, जब हमने भावनाओं में बहकर, जल्दबाजी में एक गलत कदम उठा लिया। वह एक गलत निर्णय था। इस पार्टी ने मुझ जैसे एक गरीब व्यक्ति को एक पहचान दी, ... मुझे विधायक बनाया। ...मेरा मानना है कि किसी की मित्रता के प्रभाव में आकर तथा भावनाओं में बहकर कांग्रेस छोड़ देना हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी।"

भीषण सड़क हादसे में चार की मौत, 26 अन्य घायल

जोधपुर मथानिया रोड पर बस और ट्रक में आमने-सामने हुई भिड़ंत, तीन की हालत नाजुक

- **मंडोर के ए.सी.पी. राजेन्द्र प्रसाद दिवाकर ने बताया कि, निजी बस जोधपुर से चाडी जा रही थी और ट्रक ओसियां से जोधपुर जा रहा था।**
- **बताया जा रहा है कि, ट्रक गलत दिशा से आ रहा था और 45 सीटर बस खचाखच भरी हुई थी।**

जोधपुर, 6 जनवरी (कासं)। जोधपुर के निकटवर्ती मथानिया बाइपास रोड पर ट्रक और बस के बीच आमने सामने की भीड़न्त होने से चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 26-27 लोग घायल हुए हैं। जिनमें तीन की हालत नाजुक बताई जा रही है।

सभी घायलों को मथानिया और जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में भेजा गया है। मृतकों में दो लोगों की देर शाम तक पहचान हो पाई जबकि दो अन्य की पहचान नहीं हो पाई है। दुर्घटना की जानकारी पर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और पुलिस उपायुक्त पूर्व डा. अमृता दुहन सहित कई आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। इधर घायलों की कुशलक्षेम पूछने के लिए ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा भी अस्पताल पहुँची।

एसीपी मंडोर राजेंद्र प्रसाद दिवाकर ने बताया कि, जोधपुर से चाडी की तरफ चलने वाली एक निजी बस और ट्रक में यह दुर्घटना हुई है। बस जोधपुर से होते हुए चाडी जा रही थी, वहीं ट्रक ओसियां से जोधपुर की तरफ जा रहा था। प्रथम दृष्टया गलत दिशा में जाने से दुर्घटना होना पता लग रहा है। मथानिया थानाधिकारी राजीव भादू ने बताया कि मृतकों में दो की पहचान कपूरिया निवासी नरपतसिंह एवं निंबों का तालाब निवासी भंवरलाल के रूप में हुई है।

एसीपी ने बताया कि सवारियों से भरी बस जोधपुर से चांडी जा रही थी। मथानिया के पास सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। हाईवे पर लोगों ने गाडिय़ां रोकीं और लोगों को बाहर निकाला।जोधपुर हॉस्पिटल में घायलों के साथ आए लोगों ने बताया कि हादसा काफी दर्दनाक था। भिड़ंत के बाद बस में आग लग गई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाया और बड़ा हादसा होते-होते टल गया।

कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष की दो लिस्ट जारी, पर जोशी व धारीवाल एक भी ब्लॉक अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाए

- **कांग्रेस ने शुक्रवार को जारी लिस्ट में 88 ब्लॉक अध्यक्षों के नाम घोषित किए।**
- **अभी भी ब्लॉक अध्यक्ष के 212 पद रिक्त पड़े हैं।**
- **सूत्रों के अनुसार ब्लॉक अध्यक्ष पद के लिए विधायकों की सिफारिश को तवज्जो दी गई है।**

जयपुर, 6 जनवरी (का.प्र.)। राजस्थान में कांग्रेस के नए प्रभारी सुखजिन्दर सिंह रंधावा के आने के बाद संगठन में नियुक्तियों का दौर चल रहा है और कांग्रेस ने पिछले 3 दिन में दो सूचियां जारी कर 188 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। पार्टी ने शुक्रवार को 88 ब्लॉक अध्यक्षों की एक और सूची जारी की, जबकि दो दिन पहले 100 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी। दो दिन में 188 ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। कांग्रेस में कुल 400 ब्लॉक हैं, अब भी 212 ब्लॉक बिना अध्यक्षों के हैं, जिन पर नियुक्तियां होना शेष है।

इन नियुक्तियों में विधायकों या हारे हुए नेताओं की राय को ही अहमियत दी गई है।

शुक्रवार को जिन ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, उनमें प्रमुख रूप से अजमेर के सरवाड़ में श्यामलाल बैरवा, भिनाय में गिरधारीलाल गुर्जर, मसूदा में सलीम बाबू, अलवर के कठूमर में सिब्बो गुर्जर, खेड़ली में कैलाश चंद मीणा, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में रजनीकांत खाबिया, सज्जनगढ़ में भरत सिंह लबाना, बाड़मेर के चौहटन में त्रिलोक चौधरी, सेड़वा में दीन मोहम्मद, बालोतरा में छगन जोगसन, पचपदरा में विक्रम सिंह, भरतपुर में दयाचंद पचौरी, देवर में दीनदयाल जाटव, भीलवाड़ा के रायपुर में कुलदीप त्रिवेदी, बूंदी में प्रेम शंकर राठौड़, तालेड़ा में राम किरण मीणा, चूरू के सादुलपुर शहर सीताराम प्रजापत, सादुलपुर ग्रामीण में अशोक पूनिया, सरदारशहर सिटी से जितेंद्र राजवी, सदारशहर ग्रामीण से इशर राम डूडी, सुजानगढ़ शहर से प्रदीप कुमार तोदी, दौसा के बांदीकुई ए से रामेश्वर प्रसाद मीणा, बांदीकुई से खेमराज बैरवा, श्रीगंगानगर के मिर्जेवाला से लालचंद मेघवाल, सादुलशहर अनंतराम खड़गवाल जयपुर के आदर्श नगर से संजय काला, रामगंज से गुलाम मुस्तफा, बगरू से रामावतार शर्मा, जगतपुरा से कैलाश चंद मीणा, चाकसू से भरतलाल मीणा, माधोराजपुरा से पवन कुमार खरोल, दूदू से शिवजीराम खुरड़िया, फागी से किशन दत्त दाधीच, आंधी से श्रवण लाल गुर्जर, जमवारामगढ़ से रामधन बेनीवाल, नारहेड़ा से गोकुल आर्य, फुलेरा से पुष्पा मेघवाल, रेनवाल से श्रवण लाल डिडेल, मानसरोवर से रतनलाल सैनी, सांगानेर राजीव चौधरी, झोटवाड़ा शहर से हरेंद्र पाल सिंह जादौन, विद्याधर नगर से बद्री नारायण कुमावत, पावटा से महादेव यादव, विराट नगर से महेंद्र रतवाल और जोधपुर के बिलाड़ा से महेश मेघवाल शामिल है।

इन दो सूचियों में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत 30 मंत्रियों में से 25 सितंबर की घटना के दोषी माने जाने के बाद कारण बताओ नोटिस पाने वाले दोनों मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी के विधानसभा क्षेत्रों में शुक्रवार को भी ब्लॉक अध्यक्ष नहीं घोषित किए गए हैं। झालावाड़, पाली और हनुमानगढ़ की किसी भी विधानसभा क्षेत्र का एक भी ब्लॉक अध्यक्ष अभी तक घोषित नहीं किया गया है।

वहीं मंत्री भजन लाल जाटव और राजेंद्र गुढ़ा के क्षेत्र में भी ब्लॉक अध्यक्ष घोषित नहीं हुए हैं।

मंत्री रमेश मीणा और मंत्री राजेंद्र यादव की विधानसभा में 1-1 ब्लॉक अध्यक्ष के नाम घोषित किए गए हैं। इसी तरह से गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा की विधानसभा में एक ही ब्लॉक अध्यक्ष घोषित किया गया है। दिव्या मदेरणा की ओसियां विधानसभा में भी एक ही ब्लॉक अध्यक्ष घोषित हुआ है।

इस साल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नैरो गेज पर इस तरह की ट्रेन्स चलाने की है। भारत में हिमालयी एवं अन्य ईको सैन्सिटिव क्षेत्रों में नैरो गेज पटरियां हैं। इन जगहों पर वर्तमान में डीज़ल इंजन से ट्रेनें चलायी जा रही हैं। इनमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउन्टेन रेलवे, काल्का शिमला रेलवे, मथारन हिल रेलवे, कांगड़ा वैली रेल, बिलिमोरा-वघाई रेल और मारवाड़-देवगढ़ मडरिया रेल शामिल है।

44 हाई कोर्ट...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कोर्ट की समय सीमा के तहत काम करने के सभी प्रयास कर रही है। भारत में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया कई न्यायिक फैसले का विषय रही है तथा कई याचिकाओं जजों की नियुक्ति और तबादले के महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल उठाए गए है। सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की एक बैंच ने फैसला दिया था कि सी.जे. आई. का रुख सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।

क्या नेपाल आतंकवादियों...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिए दी जा रही वित्तीय सहायता का मुकाबला करना और उस पर निगरानी रखना है।

एफ.ए.टी.एफ. के एशिया पैसिफिक क्षेत्र के अधिकारियों ने नेपाल का पहले ही दौरा कर लिया है। उनकी टीम के दौरे के बाद लोगों में इसे लेकर चिंता है कि यदि नेपाल को ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के इस देश में बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। एफ.ए.टी.एफ. की टीम के दौरे का उद्देश्य यह देखना था कि क्या नेपाल उसके द्वारा तय किए गए मानदंडों का पालन कर रहा है? एफ.ए.टी.एफ. का एशिया पैसेफिक ग्रुप (ए.पी.जी.) यह देखेना कि नेपाल ने 16 दिसम्बर 2022 तक इस दिशा में क्या प्रगति की है।

नेपाल यदि एफ.ए.टी.एफ. की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो उसे एफ.ए.टी.एफ. की काली सूची में डाल दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट अथवा ग्रे लिस्ट जैसे शब्द एफ.ए.टी.एफ. की शब्दावली में शामिल नहीं है, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग प्रायः उन देशों के लिए किया जाता है जो संगठन की सूची में शामिल है।

एफ.ए.टी.एफ. की काली सूची में ऐसे हाई रिस्क देश शामिल हैं जिन पर कार्यवाही किया जाना जरूरी होती है। वर्तमान में इस सूची में उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार शामिल हैं।

ग्रे लिस्ट उन देशों के लिए होती है जिन पर एफ.ए.टी.एफ. बारीकी से निगरानी रखता है। एफ.ए.टी.एफ. की नजर में ये वे देश हैं, जो इन्टरनैशनल मनी लॉंड्रिंग और टैरेरिस्ट फायनैंसिंग को रोकने में विफल रहे हैं और इस तरह से अपने खराब व्यवहार को लेकर ग्लोबल वॉचलिस्ट में शुमार हैं।

ये देश हैं फिलीपिंस, सीरिया, यमन, संयुक्त अरब अमीरात, उगांडा, मोरक्को, जमैका, कम्बोडिया, बुरकीना फासो, दक्षिण सूडान और टैक्स हैवन्स माने जाने वाले बारबडोस, कैमन आयलैण्ड्स और पनामा।

एफ.ए.टी.एफ. की ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिए जाने के बाद इन देशों को एक कार्य योजना प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें इस लिस्ट से बाहर निकलने की एक निश्चित समय सीमा बतायी जाती है।

द काठमांडू पोस्ट ने नेपाल राष्ट्र बैंक के एक सीनियर अधिकारी को उद्धृत करते हुए लिखा है कि "यदि नेपाल को ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया तो खतरा बहुत बढ़ जाएगा। अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर बताया कि "ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने का खतरा वास्तविक है क्योंकि मनी लॉंड्रिंग और टैरर फण्डिंग के संदर्भ में विधान और कानूनों के प्रवर्तन, दोनों में हमारे यहां त्रुटियां हैं। नेपाल ने एफ.ए.टी.एफ. के एंटी मनी लॉंड्रिंग मानकों के अनुकूल रहने वाले ऐसे 15 कानून चिन्हित किए हैं जिनमें संशोधन की जरूरत है। देश में मनी लॉंड्रिंग और टैरर फायनैंसिंग संबंधित कानून बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना अपने आप में एक चुनौती है। एशिया फैसेफिक ग्रुप की ओर से फरवरी माह में एक प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, उसके बाद ही नेपाल अपना रूख स्पष्ट करेगा।

क्या मोदी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गुजरात पुलिस ने घेर लिया और कहा कि ऊपर से आदेश है कि उन्हें अपने घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाए।

जसोदा बेन के भाई अशोक ने मीडिया को बुलाया जिसमें जशोदा बेन ने अपना दुख बयान किया कि किस तरह उन्हें अंतिम संस्कार में भाग लेने से रोका गया। एक लोकल टी.वी. चैनल ने घटना की खबर दी और हैरानी जताई कि प्रधानमंत्री का अपनी पत्नी के प्रति यह कैसा व्यवहार है। हालांकि घटना की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

पत्नी पर तेजाब फेंका

- **बताया जाता है कि, पीड़िता प्रियंका ने पति लखपत बागरिया के कहे अनुसार अपने पिता से हिस्सा नहीं मांगा था, इसलिए लखपत ने अपनी पत्नी पर तेजाब फेंक दिया।**
- **प्रियंका व उसके पिता ने लखपत बागरिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है।**

गंगापुर सिटी, 6 जनवरी (निस)। पत्नी ने पीहर पक्ष से जमीन में हिस्सा नहीं मांगा तो नाराज पति ने अपनी पत्नी पर तेजाब डाल दिया। तेजाब के हमले में पत्नी गम्भीर रूप से झुलस गई और उसे गंगापुर सिटी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला और उसके पिता ने वजीरपुर पुलिस थाने में आरोपी पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। वजीरपुर थाना क्षेत्र के सेवा गांव निवासी प्रियंका की शादी करौली जिले के सोप निवासी लखपत बागरिया के साथ हुई थी। दोनों पति-पत्नी पिछले 10 साल से गुजरात के सूरत में रह रहे थे। इसी दौरान प्रियंका के पिता ने गंगापुर सिटी के पास एक जमीन खरीदी थी। आरोपी लखपत बागरिया अपनी पत्नी प्रियंका से उसके पिता द्वारा खरीदी गई जमीन में हिस्सा मांगने का दबाव बना रहा था।

प्रियंका ने ऐसा नहीं किया तो नाराज लखपत बागरिया ने गुजरात के सूरत में ही अपनी पत्नी प्रियंका पर तेजाब डाल दिया। जिससे प्रियंका बुरी तरह झुलस गई। सूचना मिलने पर प्रियंका के पीहर पक्ष के लोग सूरत पहुंचे और प्रियंका को अपने साथ गंगापुर सिटी ले आए और घायल प्रियंका को गंगापुर सिटी के अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां प्रियंका का इलाज चल रहा है।

पीड़ित महिला के पिता सेवा गांव निवासी पप्पू बागरिया ने वजीरपुर थाने में महिला के पति लखपत बागरिया के खिलाफ दहेज के लिए मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। वजीरपुर थानाधिकारी योगेंद्र शर्मा ने बताया कि 28 दिसंबर को सूरत में पति लखपत ने पत्नी प्रियंका से 50 हजार रु. की मांग करने के साथ ही उस पर पिता की जमीन में से हिस्सा मांगने का दबाव बनाया। महिला ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिससे आरोपी पति ने महिला के मुंह पर तेजाब डाल दिया, जिससे महिला का पूरा चेहरा झुलस गया।

दिल्ली में मेयर के चुनाव में भाजपा और आप में जबरदस्त खींचतान

- **विवाद इतना बढ़ गया कि, सदन की कार्यवाही ही स्थगित कर दी गई**
- **आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि भाजपा नामित पार्षदों को वोट करने का अधिकार देना चाहती है ताकि मनमाने तरीक़े से अपना महापौर बना सके।**

नई दिल्ली, 6 जनवरी।भाजपा और आप पार्टी के पार्षदों के बीच जबरदस्त खींचतान और हंगामे के कारण दिल्ली नगर निगम के महापौर का चुनाव शुक्रवार को नहीं हो सका। महापौर के चुनाव से पहले निगम पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में जबरदस्त हंगामा हुआ जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

निगम में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने सबसे पहले उपराज्यपाल की तरफ़ से नामित पार्षदों को शपथ दिलाने के लिए एक सदस्य का नाम पुकारा जिसके बाद आम आदमी पार्टी के सबसे वरिष्ठ पार्षद मुकेश गोयल ने कहा कि यह प्रक्रिया ग़लत है। गोयल ने कहा कि सबसे पहले चुने हुए पार्षदों को शपथ दिलाई जाए उसके बाद सदन में ज़ोरदार हंगामा शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आप के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन की कार्यवाही के बाद भी दोनों दलों की और से हंगामा जारी है।

उल्लेखनीय है कि निगम के 250 वार्डों में हुए चुनाव में आप ने 15 साल से दिल्ली नगर निगम में बनी भाजपा को हराकर 134 वार्डों में जीत दर्ज की थी जबकि भाजपा को 104 वार्ड में जीत मिली थी। इस बार कांग्रेस के नौ पार्षद जीतकर आए हैं।

आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नामित पार्षदों को वोट करने का अधिकार देना चाहती है ताकि मनमानी तरीक़े से अपना महापौर बना सके।

राज्य सभा सांसद संजय सिंह, विधायक सौरभ भारद्वाज और राज्य सभा सदस्य सुशील गुप्ता ने शुक्रवार को एक इस मामले में यहाँ सिविक सेंटर में संवाददाता सम्मेलन किया।

कर्नाटक में चला पर तमिलनाडू में नहीं चल पा रहा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याद दिलाती रहती है कि इस बिन्दु पर वर्तमान स्थिति यथावत बनी रहेगी तथा मंदिरों से सरकारी नियंत्रण नहीं हटेगा।

तमिलनाडु सरकार का "हिन्दू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एनडाउमेंट्स (एच.आर. एंड सी.ई.) विभाग हिन्दू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एनडाउमेंट्स एक्ट, 1959 के तहत, राज्य के 44,000 का प्रबंधन करता है। तमिलनाडु सरकार के सूत्रों का कहना है कि "सरकार मंदिरों को मुक्त करने के पूरे तरह खिलाफ है क्योंकि ऐसा करने से कई प्रकार के गलत तौर-तरीकों तथा मंदिर के पैसे के दुरुपयोग का रास्ता खुल जायेगा।"

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि सरकार किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, जैसा कि गलत तरीके से चित्रित किया जा रहा है। बात केवल यह है कि सरकार यह चाहती है कि मंदिरों की प्रतिष्ठा समानतावादी स्थलों के रूप में, असमानता-रहित स्थलों के रूप में रहे। किसी का नाम लिये बिना, उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी (द्रमुक) को नापसंद करते हैं, द्रमुक को धर्म-विरोधी पार्टी के रूप में चित्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसी धर्म के खिलाफ नहीं है लेकिन धर्मान्धता या धार्मिक कट्टरता के खिलाफ है। स्टालिन ने कहा, "यह सरकार धर्म या जाति, मंदिर या भगवान के बीच को भेदभाव नहीं करती है। हम राज्य के सभी धार्मिक संस्थाओं का ध्यान रख रहे हैं। यही कारण है कि लोग अब भी हमारी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। जो लोग हमारी आलोचना करते हैं, वे इस क्रिया-कलाप के जरिये, यह महसूस करेंगे कि हमारे सारे प्रयास समतावादी समाज की सुनिश्चित करने के लिये हैं।"

1500 आदि द्रविड़ तथा आदिवासी मंदिरों तथा इतनीसंख्या में तमिलनाडु के गाँवों में बने मंदिरों में से प्रत्येक को मरम्मत एवं पुनरुद्धार के लिये 2 लाख रू. सरकारी अनुदान देते हुये, मुख्यमंत्री ने कहा कि वे "हिन्दू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एन्डाउसमेंट्स डिपार्टमैंट को, गृह विभाग जो स्वये उनके पास है, तथा उद्योग विभाग के बाद, सर्वाधिक महत्व दे रहे हैं ताकि वह बड़ी संख्या में कल्याणकारी कार्य शुरु कर सके।

एच.आर. एवं सी.ई. डिपार्टमैंट के तत्वावधान में आयोजित एक समारोह में बोलते हुये, मुख्यमंत्री ने कहा, "मेरा लक्ष्य सभी विभागों में बराबर विकास को सुगम बनाना है। लेकिन जो लोग इस बात की समझ नहीं रखते तथा द्रविड़वाद को नापसंद करते हैं, हमें धर्म-विरोधी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम धार्मिक कट्टरता एवं धर्मोन्माद के खिलाफ हैं, धर्म के खिलाप नहीं है।"

उन्होंने कहा, "आज सरकार ने 2500 मंदिरों के पुनरुरुद्वार के लिये 50 करोड़ रू. जारी किये हैं। डी.एम.के. के सत्ता में आने के बाद, मंदिरों के विकास के लिए अनगिनत कामों की शुरुआत हुई है।"

सरकार द्वारा गठित की गई एक विशेषज्ञ समिति ने सरकार को सुझाव दिया कि सरकार एच.आर. एंड सी.ई. विभाग के तहत संचालित करीब 44,000 मंदिरों की मरम्मत, पुनरोद्धार तथा भक्तों की सुख-सुविधाओं का काम शुरु कराये।

इस मार्गदर्शन के अनुसार, करीब 3,986 मंदिरों के पुनरोद्धार के लिये 100 करोड़ रू. मंजूर कर दिये गये। सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान विधानसभा में की गई 112 में से 91 घोषणाओं को क्रियान्वित कर चुकी है। स्टालिन ने जानकारी देते हुये आगे कहा कि वर्ष 2022-23 के दौरान की गई 165 में से 132 घोषणाओं पर काम चल रहा है। स्टालिन ने कहा कि द्रमुक सरकार हिन्दू मंदिरों या धर्म के खिलाफ नहीं है।

स्टालिन ने कहा, "मंदिर हमारी कला एवं संस्कृति के प्रतीक, परिष्कृत स्थापत्य के प्रमाण एवं कलात्मक उत्कृष्टता के उदाहरण हैं।

इसलिये, हम उनका संरक्षण कर रहे हैं तथा ऐसा करना हमारा कर्तव्य है।" उन्होंने कहा कि सरकार ने मंदिरों में अर्चना करने के लिये तमिल भाषा के प्रयोस के लिये रास्ता सुगम बनाने के काम में लगी हुई है।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, "लोगों, जिनके साथ जाति के नाम पर भेदभाव होता है, के साथ ही नहीं, बल्कि मंदिरों के साथ भी- गाँव के मंदिरों, धनवान मंदिरों, धनहीन मंदिरों के रूप में भेदभाव नहीं होना चाहिये। यह सरकार बिना किसी पूर्वाग्रह के, इन सब की मदद कर रही है।"

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908